उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एकीकृत ग्रामीण कार्यक्रम का कार्यान्वयन

2366. **श्री रशीद मसूद** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एकीकृत विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में योजनाओं का कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इन प्रदेशों में इन योजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि को दूसरी योजनाओं में व्यय कर दिया गया है ;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई सूचना मिली है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) जी नहीं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ने गत वर्ष के दौरान भौतिक और वित्तीय दोनों प्रकार से अर्थात् सहायता किए गए परिवारों की संख्या और निधियों के उपयोग के रूप में उन्हें दिए गए लक्ष्यों से अधिक उपलब्धि प्राप्त की है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उनकी उपलब्धियां भौतिक दृष्टि से 105.45 प्रतिशत और 108.53 प्रतिशत तथा निधियों के उपयोग की दृष्टि से 11.06 प्रतिशत और 108.31 प्रतिशत है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य तेलों की प्रति व्यक्ति खपत

2367. **श्री रशीद मसूद** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में खाद्य तेलों की प्रति व्यक्ति खपत विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ब्यौरा है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी हां।

(ख) तेल वर्षों 1983-84 से 1985-86 तक प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत खपत विश्व के 11 कि० ग्रा० के औसत की तुलना में लगभग 9.5 कि० ग्रा० है।

उपभोक्ताओं के संरक्षण की योजना

2368. **श्री रशीद मसूद** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में उपभोक्ताओं को संरक्षण देने के लिए योजना बनाकर उसे राज्य सरकारों को तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को भेजा है और यदि हां, तो उसकी क्या रूपरेखा है ; और

(ख) इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) सरकार उपभोक्ता संरक्षण के कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता देती है। उपभोक्ता कल्याण को 20 सूत्री कार्यक्रम-86 में शामिल किया गया है। उपभोक्ता को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक उपभोक्ता संरक्षण कानून, अर्थात्

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 अधिनियमित किया गया है। अधिनियम में केन्द्र तथा राज्यों पर विशेष जिम्मेदारियां डाली गई है। केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करने से संबंध रखता है। राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का संबंध राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदों, जिला प्रतितोष मंचों और राज्य आयोग की स्थापना करने से है। योजना आयोग, सातवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के लिए उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम को एक योजना स्कीम के रूप में मानने के लिए सहमत हो गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में सांविधिक संस्थान स्थापित करने के लिए निधियां राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपनी योजना स्कीमों में तथा यदि आवश्यक हो तो अंतरक्षेत्रीय सहायोजनों/बचतों के माध्यम से मुहैया की जानी है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत परिकल्पित सांविधिक संस्थानों की स्थापना के लिए आवश्यक प्रबंध करें। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है।

Construction of Narmada Sagar Project

2369. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether the construction of the Multi-purpose Narmada Sagar Project has since commenced;

(b) if not, what are the reasons therefor; and

(c) by when the work is likely to commence?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI B. SHANKARANAND): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

910 RS-5.

Displacement by Sardar Sarovar Project

2370. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state

(a) whether it is a fact that more than 600 families in nine villages of Akkalkuva taluka in Dhule District would be among the first victims to be affected by the Sardar Sarovar multi-purpose project;

(b) whether Government have allotted alternate accommodation to the affected families and given financial assistance to them; and

(c) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI B. SHANKARANAND): (a) About 600 families from 10 villages in Akkalkuva taluka are likely to be affected in the first stage.

(b) and (c) Gujarat Government has made arrangements to resettle the oustees from the two villages who are willing to resettle in Gujarat. An Inter-State Task Force is to ensure their speedy and effective resettlement.

Impact of Failure of Monsoon on Kharif Crop in Northern India

2371. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the press report which appeared in 'The Hindustan Times" of the July 30, 1987 to the effect that disaster stares the farmers of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Rajasthan in the face;

(b) whether it has also been stated therein that kharif crops were withering because of the complete monsoon failure and Pong-Dam level was the lowest ever; and

(c) if so, what steps are being taken by Government to help the farmers?